

प्रेषक,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 16 जुलाई, 2012

विषय— राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी की जगतपुर पेयजल योजना (एकल ग्राम योजना) की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 962/ DPR-79 (IV)/2011-12 दिनांक 16-01-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी की जगतपुर पेयजल योजना (एकल ग्राम योजना) के अनुमानित लागत ₹ 130.30 लाख के प्रस्तुत किये गये आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त ₹ 91.26 लाख की धनराशि निर्माण कार्य के अन्तर्गत औचित्यपूर्ण पाई है, इसी प्रकार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार ₹ 35.74 लाख इस प्रकार कुल ₹ 127.00 लाख (₹ एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) की लागत के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (I)— उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय, उत्तराखण्ड को प्राप्त होने वाली धनराशि में से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा मात्र प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है तथा व्यय हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
- (II)— कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (III)— कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (IV)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।
- (V)— एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- (VI)— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (VII)— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का निरीक्षण भलीभाँति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (VIII)— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

क्रमश—2—पर—

(2)

(IX)– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(X)– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(XI)– योजना पर सेन्टेज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(XII)– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(XIII)– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(XIV)– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

(XV)– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

(XVI)– कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू गठित कर लिया जाय जिसमें defect liability clause का प्राविधान भी सुनिश्चित कर लिया जाय।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 216/XXVII (2)/2012 दिनांक 10-07-2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जी० बी० ओली)
संयुक्त सचिव,

पृष्ठांकन संख्या: 275(i)/उन्तीस(2)/12-2(127पे०)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमायू मण्डल।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, नैनीताल।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
13. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मरिमा राँकली)

उप सचिव